



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

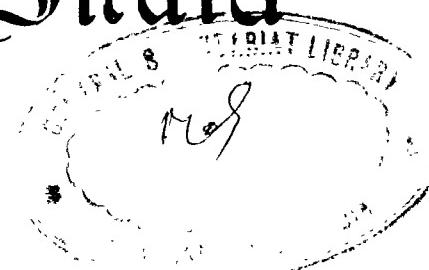
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2000/चैत्र 31, 1922
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2000/CHAITRA 31, 1922



जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 342 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ मंलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षण सहायता) विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी आर-12016/18/99-पीई-1]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

मुरगांव पत्तन न्यास

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (शिक्षण सहायता)

विनियम, 2000

विद्यमान मुरगांव पत्तन कर्मचारी (बाल शिक्षण भत्ता) विनियम, 1974 और मुरगांव पत्तन कर्मचारी (शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1974 तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 124(2) की शर्तों का अधिक्रमण करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल एतद्वारा “मुरगांव पत्तन कर्मचारी (शिक्षण सहायता) विनियम, 2000 संशोधित” शीर्षक के तहत उपरोक्त विनियमों के दोनों सेटों को समेकित और अद्यतन करता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1) ये विनियम मुरगांव पत्तन कर्मचारी (शिक्षण सहायता) विनियम, 2000 कहलाएंगे।
- 2) ये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. उपयोजन :-

- 1) ये विनियम आकस्मिक या दिहाड़ी या अंशकालिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के अतिरिक्त मंडल के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।
- 2) इन आदेशों के तहत भारत स्थित केन्द्र/राज्य सरकार में वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त मंडल कर्मचारी उन केन्द्र/राज्य सरकार अथवा वाह्य नियोक्ता से, प्रतिनियुक्त अथवा वाह्य सेवा में यदि इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान हों तो, शिक्षण सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. परिभाषाएं :-

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में —

- 1) मंडल का अर्थ वही होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में दिया गया है।
- 2) कर्मचारी का तात्पर्य मंडल कर्मचारी से है।
- 3) बाल का तात्पर्य मंडल कर्मचारी के शुल्क से है, जिसमें कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित सीतेला बच्चा तथा गोद लिया बच्चा भी सम्मिलित है।
- 4) “हायर सेकेण्डरी अथवा सीनियर सेकेण्डरी कक्षा” का तात्पर्य कक्षा XI तथा कक्षा XII से है तथा इसमें प्री—यूनिवर्सिटी क्लास जैसे 10+2+3 के तहत XII के समतुल्य तक की कक्षाएं अथवा इण्टरमीडिएट कालेज, तकनीकी कालेज या पॉलिटेक्निक की प्रथम वर्ष की कक्षा सम्मिलित हैं, बताते कि इन कक्षाओं में प्रवेश लेने से पूर्व बच्चे ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा पास न की हो बल्कि सेकेण्डरी अथवा समतुल्य पास किया हो।

- 5) *प्राथमिक कक्षा* का तात्पर्य कक्षा 1 से IV तक हैं, परन्तु इसमें किंडरगार्टन या नर्सरी कक्षा सम्मिलित नहीं है ।
- 6) मान्यताप्राप्त स्कूल का तात्पर्य सरकारी स्कूल या कोई शिक्षण संस्थान, चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा गैर- मान्यताप्राप्त या मान्यताप्राप्त शिक्षण प्राधिकरण है जिसका न्यायिक क्षेत्र वहां हो जहां वह संस्थान विद्यमान है । इन विनियमों के प्रयोजनार्थ सीनियर स्तर की शिक्षा को स्कूली स्तर की शिक्षा माना जाएगा ।
- 7) *सेकेण्डरी कक्षा* का तात्पर्य कक्षा V से X तक है ।
- 8) *शिक्षण शुल्क* का तात्पर्य देय और वास्तव में भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क है । इसमें ये सम्मिलित है :-
- (क) विज्ञान शुल्क
 - (ख) प्रयोगशाला शुल्क, यदि विज्ञान शुल्क पृथक से प्रभारित नहीं की जाती है ।
 - (ग) अतिरिक्त चयनित विषय के रूप में कृषि के लिए प्रभारित विवेश शुल्क तथा
 - (घ) संगीत जैसे विषय के लिए प्रभारित अन्य शुल्क, जिन्हें नियमित स्कूल/कलेज पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता हो/ अथवा कार्य अनुभव की योजना के तहत प्रेक्षिकल कार्य वाला विषय हो ।

तथापि यदि विज्ञान वर्ग के शिक्षार्थी पर प्रभारित शिक्षण शुल्क गैर-विज्ञान वर्ग के शिक्षार्थी से अधिक है, तो विज्ञान शुल्क, पृथक रूप से प्रभारित करने पर भी, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ शिक्षण शुल्क में सम्मिलित नहीं होंगे ।

व्याख्या :-

शिक्षण शुल्क में ये सम्मिलित नहीं है :-

- क) आंतरिक विज्ञान नियि प्रभार
- ख) पुस्तकालय शुल्क
- ग) खेल शुल्क
- घ) प्रवेश शुल्क तथा
- ड) अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि शुल्क

सामान्य शर्तें

4. पात्रता :-

- (1) इन विनियमों के विनियम सं. 11 से 24 के प्राक्षानों के अधीन मंडल के सभी कर्मचारी, सिवाय आकस्मिक या दिहड़ी या अंशकालिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के, बिना वेतन सीमा के बाल शिक्षण सहायता, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा हॉस्टल सब्सिडी पाने के पात्र होंगे ।

5(1) यदि पति और पत्नी दोनों मंडल के कर्मचारी हैं, और इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं तो बाल शिक्षा भत्ता या शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी, जैसा भी मामला हो, उनमें से केवल एक को ही मिलेगा ।

5(2) यदि किसी कर्मचारी की पत्नी या पति मंडल सेवा के बाहर नियोजित है तो इन विनियमों के तहत कर्मचारी भत्ता या प्रतिपूर्ति या सब्सिडी प्राप्त करने का तभी पात्र होगा जबकि उसकी उसके पत्नी या पति को उसके नियोजक द्वारा ऐसे कोई भत्ता या प्रतिपूर्ति का लाप्त प्राप्त न हो और कर्मचारी से इस बाबत वचन पत्र प्राप्त किया गया हो ।

6(1) किसी कर्मचारी को जब कि वह डयूटी में हो या निलम्बित हो या छुट्टी (असाधारण अवकास सहित) में हो तो वह बात शिक्षा भत्ता या शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र होगा ।

बताते कि किसी अवधि के दौरान जिसे अकार्य दिवस के रूप में माना गया है, कर्मचारी 36 अवधि के लिए भत्ता/प्रतिपूर्ति/सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।

6(2) यदि किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी मर जाता है या सेवा से सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, निर्युक्ति, निष्काशन या बरखास्तगी के कारण सेवा में नहीं रहता तो घटना घटित होने वाले शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता या प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी ।

7. बाल शिक्षा भत्ता अथवा हॉस्टल सब्सिडी मात्र 5 वर्ष तथा 20 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बच्चों के लिए ग्राह्य होगी, जबकि शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति मात्र 5 वर्ष तथा 25 वर्ष के बीच की आयु सीमा के बच्चों के लिए ग्राह्य होगी भले ही वे शैक्षणिक सत्र के दौरान बीच में ही 20 वर्ष या 25 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो; पूरे करते हों। कोई भी कर्मचारी एक ही कक्षा में दो शैक्षणिक सत्रों से अधिक बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।

8. इन विनियमों के तहत दिनांक 31.12.1987 तक जन्मे 3 बच्चों के लिए सहायता उपलब्ध रहेगी और उसके बाद जन्मे 2 बच्चों तक ही सीमित होगी ।

9. यदि बच्चा नियमित रूप से स्कूल/कालेज जाता है तो ही कोई कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ता शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र होगा ।

परन्तु यदि कही कोई बच्चा स्कूल/कालेज से बिना उचित अवकाश के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है, भले ही उसका नाम स्कूल/कालेज के रजिस्टर में रहें, इस प्रकार के भत्ते, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी जाएगी ।

10. किसी भी कर्मचारी को इसके बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति या हॉस्टल सब्सिडी, इस तथ्य के बावजूद कि उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी, देय होगी परन्तु यदि फौशियप दी जाती है तो वास्तव में अदा किए गए शुल्क तक ही शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/हास्टल सब्सिडी देय होगी ।

11. बाल शिक्षा भत्ता

11(1) कर्मचारी की तैनाती नहीं है और/अथवा जहां वह रहता है वहां उचित स्तर का स्कूल/कालेज नहीं है वहां से दूर यदि उसे अपने बच्चे को मजबूरन स्कूल/कालेज भेजना पड़ रहा हो, तो वह कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

उदाहरण 1:- * क * का मुख्यालय हारबर/वास्को द गामा है और वह मडगांव में रहता है । यदि उसका बच्चा हारबर/वास्को द गामा या मडगांव स्थित स्कूल/कालेज में पढ़ता है तो उसे भत्ता देय नहीं होगा ।

उदाहरण 2. उपरोक्त विनियम 11(1) के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ता तभी देय होगा जबकि उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानंतरण होने पर पुराने स्थान पर बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा जारी करने हेतु अपने बच्चे को सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी कक्षाओं के अंतिम वर्ष में पढ़ाने के लिए रखता है ।

11(2) इस आदेश के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित स्कूल/कालेजों को अपेक्षित स्तर के स्कूल/कालेज नहीं माना जाएगा ।

क) जहां तक एग्लों इंडियन बच्चे का संबंध हैं, एग्लों इंडियन समुदाय द्वारा न घलाए गए स्कूल/कालेज या इंडियन काउन्सिल आफ सेकेण्डरी एडुकेशन के काउन्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाजामिनेशन से सम्बद्ध न हो ।

ख) कोई स्कूल जो किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय द्वारा चलाया जा रहा है और इस स्कूल/कालेज में धार्मिक अनुदेश अनिवार्य रूप से दिए जा रहे हों, जिसके कारण उसके धार्मिक सिद्धात बच्चे को रोकते हों ।

ग) ऐसा स्कूल/कालेज जहां बच्चे की भाषा से अलग भाषा में शिक्षा दी जाती है ।

उवाहरण 1) :- बच्चे की भाषा, इससे पूर्व बच्चा जहां शिक्षा प्राप्त कर रहा वहां की माध्यम की भाषा होगी और यदि बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिला ले रहा हो तो उसकी भाषा इसके जन्म की मातृभाषा या अपनाई गई भाषा होगी ।

उवाहरण 2) :- बाल शिक्षा भत्ते की ग्राह्यता का निर्णय स्कूल/कालेज के स्तर यथा, प्राइमरी, सेकण्डरी या हायर सेकण्डरी या सीनियर सेकण्डरी तथा शिक्षा का माध्यम और बच्चे की भाषा के संदर्भ में करना होगा, न कि किसी विशेष संस्था में विशेष विषय नहीं होने के कारण से ।

12. मण्डल के कर्मचारी को, जो ऐसे स्थान में है जहां अपेक्षित स्तर का कोई स्कूल/कालेज नहीं है, भत्ता तभी स्वीकार्य होगा जब कि बच्चे को उसके निवास स्थान से स्कूल/कालेज ले जाने और दिन भर के लिए स्कूल बंद होने के न कि बहुत देर बाद बच्चे को वापस लाने के लिए सुविधाजनक बस या ट्रेन नहीं है और इस प्रकार बस/ट्रेन से सफर के लिए एक से अधिक घटा नहीं लगना हो ।

13. यदि किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान से, जहां अपेक्षित स्तर का स्कूल/कालेज ही स्थान्तरित किया जाता है और यदि उसे फहले स्थान पर अपने किसी बच्चे के लिए भत्ता मिलता था तो जब तक बच्चा उस स्कूल/कालेज में जड़ता रहेगा तब तक उसे भत्ता मिलता रहेगा ।

14. यदि किसी कर्मचारी के बच्चे को उस स्थान में जहां कर्मचारी तैनात/निवास करता है, अपेक्षित स्तर के स्कूल/कालेज में कोई रिक्ती न होने या अन्य कोई कारण से प्रवेश नहीं मिलता है और बच्चे को कर्मचारी के तैनात/निवास स्थान से दूर स्कूल/कालेज जाना पड़ता हो तो वह कर्मचारी उसके स्थान पर अपेक्षित स्तर का स्कूल/कालेज न होने के कारण भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

उदाहरण :- स्कूल/कालेजमें रिक्ति की उपलब्धता का विनिश्चय स्कूल/कालेज में बच्चे के प्रवेश के समय मौजूदा स्थिति के संदर्भ में भजे वह शुरुआत में हो अथवा मध्य सत्र में हो उस क्षेत्र के सक्षम शिक्षण प्राधिकारी से विचार विमर्श के बाद किया जाएगा न कि स्कूल/कालेज प्राधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर ।

15. इन भत्तों को प्राप्त करने वाला कर्मचारी इन भत्तों को किसी भी अवधि के दौरान प्राप्त करने का अधिकारी होगा परन्तु जो चार माह से अधिक नहीं होगा :

1. जबकि वह उस बच्चे के पास छुट्टी में, निलंबन के दौरान या अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान जाकर रहता है, जिसके लिए भत्ता आहरित किया गया है ।
2. जबकि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि बिमारी के कारण बच्चे को पढ़ाई से दूर रखा गया है और बच्चा कर्मचारी के पास आकर रहने लगे, और
3. जब बच्चा छुट्टियों के दौरान कर्मचारी के पास आकर रहता है, बशर्ते कि स्कूल/कालेज के पंजी में बच्चे का नाम रहता हो ।

16. प्राथमिक, सेकेण्डरी तथा हायर सेकेण्डरी कक्षाओं (कक्षा 1 से XII) के लिए प्रति माह प्रति बालक 100 रु. की दर से भत्ता दिया जाएगा ।

17. (1) छुट्टियों के दौरान कोई शिक्षण शुल्क का भुगतान न किए जाने के बावजूद पूरे वर्ष भर कर्मचारी को भत्ता दिया जाएगा ।

(2) सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके मामले में कर्मचारियों को उस माह के अंत तक भत्ता दिया जाएगा जिस माह परीक्षा समाप्त होती है अथवा उस माह की समाप्ति तक जब तक कि स्कूल/कालेज शुल्क प्रभारित होते हैं जो भी बाद में हो ।

(3) सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा इण्टरमीडिएट परीक्षा बोर्ड या प्रीयूनिवर्सिटी परीक्षा में जो बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ है, परन्तु अपनी पढ़ाई जारी रखा हुआ है उसके मामले में कर्मचारियों को मध्यवर्ती छुट्टी अवधि तक के लिए भत्ता दिया जाएगा बशर्ते कि छुट्टी अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किया गया हो ।

शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति

18. कर्मचारी अपने बच्चे के लिए देय तथा वास्तव में भुगतान किए गए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का पात्र है, बशर्ते उसे इन विनियमों के तहत कोई बाल शिक्षा भत्ता स्वीकार्य न किया गया हो ।

19. कर्मचारी द्वारा अपने बच्चे के लिए देय तथा वास्तव में भुगतान किए गए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित सीमा तक की जाएगी :

- क) कक्षा 1 से X ————— रु. 40 प्रतिमाह प्रति बच्चा
- ख) कक्षा XI से XII ————— रु. 50 प्रतिमाह प्रति बच्चा
- ग) कक्षा 1 से XI ————— शारीरिक अंपग तथा मंदबुद्धि बालक
रु. 100 प्रतिमाह प्रति बच्चा

नोट :- कक्षा IX से XII तक विज्ञान विषय लेकर पढ़ने वाले बच्चों के मामले में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रु. 10/- प्रतिमाह की सीमा तक विज्ञान शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

20. किसी यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे या प्री यूनिवर्सिटी/ इण्टरमीडिएट कालेज की द्विवर्षीय कक्षा अथवा इंजीनियरिंग के टेक्नीकल कालेज/मेडिकल या पॉलिटेक्नीक की तीन वर्षीय कक्षा या पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेज द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति यद्यपि

पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी जो कि सरकारी कालेज द्वारा पत्राचार कक्षाओं सहित संगत कक्षाओं विहित दरों की सीमा के अधीन होंगी ।

उन मामलों में जहां संशोधित शिक्षा पद्धति के अनुसार पॉलिटेक्निक में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 10 वीं कक्षा न्यूनतम योग्यता है और विद्यार्थी संशोधित शिक्षा पद्धति के X वीं कक्षा उत्तीर्ण कर पालिटेक्निक में प्रवेश लेता है तो उपरोक्त कोर्स के प्रथम, द्वितीय तर वर्ग की कक्षा के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

21. इन विनियमों में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी कर्मचारी के शारीरिक अद्यवा मंदबुद्धि बालक की देय और भुगतान की गई शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति निष्पलिखित अधीन की जाएगी :—

क) वह संस्थान, जहां बच्चा पढ़ाई कर रहा है वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संप्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त या अनुमोदित या सहायता प्राप्त है ।

ख) प्रभारित शुल्क केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा, जैसी भी यिह या अनुमोदित है ।

उदाहरण :— यदि संस्थान मान्यताप्राप्त या अनुमोदित या सहायता प्राप्त है परन्तु प्रभारित शुल्क या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा अनुमोदित नहीं हैं तो शुल्क रु. 50/- प्रतिमासीमित होगा ।

22. हॉस्टल सबिसडी

स्थानान्तरण के कारण कर्मचारी के तैनाती/या निवास से दूर आवासीय स्कूल/कालेज के हॉस्टल में उसे अपने बच्चे को रखना पड़ता है तो उसे रु. 300/- प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से सबिसडी की जाएगी ।

तथापि, यदि स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व हास्टल में प्रवेश लिया गया है और यह प्रवेश स्थान की प्रत्याशा में किया गया हो तो हॉस्टल सबिसडी स्थानान्तरण की तारीख से प्रभावी होगी ।

23. हॉस्टल सबिसडी की अदायगी, राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों, मेंजहां $10 + 2 + 3$ फ अपनाई गई है, $10 + 2$ स्तर तक और अन्य राज्यों और संघ राज्यों में हायर सेकेण्डरी तथा सी-सेकेण्डरी स्तर तक की जाएगी, भले ही बच्चा केन्द्रीय विद्यालय या अन्य पंजीकृत स्कूल/कालेज में रहा हो ।

24. यदि कर्मचारी ने बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता लिया हो तो हॉस्टल सब्सिडी स्वीकार नहीं की जाएगी ।

बाल शिक्षा भत्ता का भुगतान, शिक्षण शुल्क और हॉस्टल सब्सिडी की प्रति पूर्ति की प्रक्रिया

25. कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ता का दावा करने तथा शिक्षण शुल्क या हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने के लिए विहित प्रपत्र 1,2,3 तथा 4 में जो भी मामला हो, एक प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष को प्रथम बार दावा करने तथा बाद में प्रत्येक वर्ष मार्च और जुलाई माह में जमा करना होगा । यदि कर्मचारी स्वयं विभागाध्यक्ष है तो वह अपने उच्च अधिकारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

नोट :— कर्मचारी को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उस संस्थान के प्रमुख का, जहां उसका बच्चा पढ़ रहा है, प्रमाणपत्र पर जोर नहीं दिया जाएगा । तथापि, प्रथम दावा स्वीकार करते समय, स्कूल/कालेज द्वारा दी गई नकद प्राप्ति रसीद या बैंक क्रेडिट बाउचर का अध्यपत्ता, यदि कर्मचारी द्वारा शिक्षण शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य में शिक्षण शुल्क बैंक द्वारा जमा किया गया हो तो, प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा ।

इसके पश्चात के अवसर पर कर्मचारी से इस आशय का वचन पत्र स्वीकारा जाएगा कि वह शिक्षण शुल्क आदि पर व्यय कर रहा है । कर्मचारी को यह भी प्रमाणित करने के लिए कहा जाएगा कि उसका बच्चा/उसके बच्चे वास्तव में मान्यताप्राप्त स्कूल/कालेज में पढ़ रहे हैं और वह वास्तव में शिक्षण शुल्क पर व्यय कर रहा है ।

26. अपने विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्षों के मामलों में अगला उच्च अधिकारी यथा, अध्यक्ष यथावश्यक जांच के बाद कर्मचारी को ग्राह्य भत्ते की रकम को सूचित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिसके आधार पर भत्ता दिया जाएगा ।

परन्तु बाल शिक्षा भत्ता के मामले में औपचारिक आधार पर भत्ता प्राप्त करने की स्वीकृति ऊपर दिए गए संत्यापन के लंबित रहते हुए तीन माह की अल्प अवधि के लिए कर्मचारी से यह वचन प्राप्त करने के बाद कि संत्यापन के बाद यदि यह पाया जाता है कि तैनाति/निवास स्थान या विनियम 12 में बताए गए स्थानों के समीप यदि अपेक्षित स्तर का स्कूल/कालेज नहीं हो तो वह दिये गए भत्ते को वापस करेगा ।

परन्तु यह भी कि विभागाध्यक्ष या अन्य उच्च अधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, स्वविवेक से इन आदेशों के तहत सहायता ग्राह्य के बारे में, आवधिक अंतरालों पर जांच करवाएंगा ।

27. विभागाध्यक्ष वेतन चिट्ठे में प्रमाणित करेंगे कि ऊपर विनियम 26 में बताए गए प्रमाणपत्रों को वेतन चिट्ठे में चढ़ाए गए कर्मचारियों से प्राप्त किए गए हैं ।
28. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किए गए कर्मचारी को नए स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा यदि वह बाल शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र है ।
29. विभागाध्यक्ष को ऐसे कर्मचारियों के प्राप्त दावों की स्वीकृत/अस्वीकृत तथा प्रतिपूर्ति का उचित रिकाई रखना होगा और पत्तन कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों और सूचनाओं शैक्षणिक संस्थाओं से उनके द्वारा किए गए दावों के समर्थन में रसीदें तथा अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, सहित वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ।

30. विनियमों का निर्वचन :-

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका है तो उसका निर्णय मंडल द्वारा किया जाएगा ।

31. निरसन और व्यावृति :-

इन विनियमों के अनुरूप सभी नियम और समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेश, जो इन विनियमों के आरंभ होने के तत्काल पूर्व प्रभावी हो, को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

परंतु कि प्रतिस्थापित विनियमों के तहत बनाया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई को इन विनियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत बनाई गई अथवा की गई कार्रवाई माना जाएगा ।

32. इन विनियमों के उपयोजन के लिए अपनाए जाने वाले केन्द्र सरकार के आदेश/निदेश/नियम :-

आगामी विनियमों के उपयोजन तथा ऐसे मामले जिनका इन विनियमों में विचार नहीं किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवाओं (शिक्षा सहायता) आदेश, 1988 तथा समय — समय पर इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों/निदेशों को, जब तक इन विनियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं और मंडल द्वारा समय — समय पर निर्धारित ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए अपनाए जाएंगे ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2000

G.S.R. 342(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees' (Educational Assistance) Regulations, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao Port and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette

[F No PR. 12016/18/99-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

MORMUGAO PORT TRUST
S C H E D U L E
MORMUGAO PORT EMPLOYEES' (EDUCATIONAL
ASSISTANCE) REGULATIONS, 2000

In supercession of the existing Mormugao Port Employees' (Children's Education Allowance) Regulations, 1974 and the Mormugao Port Employees' (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1973 and in terms of Section 124(2) read with Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby consolidates and updates both the sets of the aforesaid Regulations under the revised title "The Mormugao Port Employees (Educational Assistance) Regulations, 2000.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (1) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Educational Assistance) Regulations, 2000.
- (2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. APPLICATIONS:

- (1) These Regulations shall apply to all employees of the Board, except persons in casual or daily-rated or part-time employment.

(2) Employees of the Board deputed to Central/State Government on foreign service in India would be eligible to drawal of educational assistance under these orders from such Central/State Government or foreign employer, provided provision to this effect is expressly made in the terms of deputation or foreign service.

3. DEFINITIONS: In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(i) 'Board' shall have the same meaning assigned in the Major Port Trusts Act, 1963.

(ii) 'Employee' means an employee of the Board.

(iii) 'Child' means a child of an employee of the Board and includes a step-child and an adopted child, who is wholly dependent on the employee.

(iv) 'Higher Secondary or Senior Secondary Classes' means Classes XI and XII and includes Classes upto the equivalent of XII under the 10+2+3 scheme like Pre-University class or the first year class of an Intermediate College, a Technical College, or a Polytechnic, provided the child has passed the Secondary or equivalent but not the Higher Secondary Examination before joining such class.

(v) 'Primary Classes' means Classes I to V but does not include Kindergarten or Nursery classes.

(vi) 'Recognised School/college' means Government school/college or any educational institution, whether in receipt of Government aid or non-recognised by the Central or State Government or Union Territory Administration or by a University or a recognised educational authority having jurisdiction over the area where the institution is situated. For the purpose of these Regulations, education upto the senior level shall be treated as school/college education.

(vii) 'Secondary Classes' means Classes VI to X.

(viii) 'Tuition Fee' means tuition fee payable and actually paid, and includes: -

- (a) Science fee.**
- (b) Laboratory fee, in case Science fee is not separately charged.**
- (c) Special fee charged for agriculture as an elective additional subject and**
- (d) Any fee charged for subjects like music, which are taught as part of the regular school/college curriculum or subject requiring practical work under the programme of work experience.**

Provided that if tuition fee charged from a Science student is higher than that charged from a non-science student, science fee, though separately charged, shall not be included in the tuition fee for the purpose of these Regulations.

EXPLANATION:

"Tuition Fee" does not, however, include –

- (a) Domestic Science fund charges**
- (b) Library fee**
- (c) Games fee.**
- (d) Admission fee and**
- (e) Extra-curricular activity fee.**

GENERAL CONDITIONS:

4. ELIGIBILITY:

- (1) Subject to the provisions of Regulation No.11 to 24 of these Regulations, all employees of the Board, except persons in casual or**

daily-rated or part-time employment, without any pay limit shall be eligible to draw children's educational assistance, reimbursement of tuition fee and hostel subsidy.

5(1) In case both wife and husband are employees of the Board and are governed by the provisions of these Regulations, the Children's Educational Allowance or Reimbursement of Tuition Fee or Hostel Subsidy as the case may be shall be admissible to one of them only.

5(2) In case the wife or husband of an employee is employed outside the Board's service, the employee shall be able to draw the allowance or reimbursement or subsidy under these regulations, only if his/her spouse is not entitled to the benefit of any such allowance or reimbursement or subsidy from his/her employer and a declaration to that effect shall be obtained from the employee.

6 (1) The Children's Educational Allowance or the Reimbursement of Tuition Fees or Hostel Subsidy shall be admissible to an employee while he/she is on duty or is under suspension or is on leave (including extraordinary leave).

Provided that during any period, which is treated as "Dies-non", the employee shall not be eligible for the allowance/reimbursement /subsidy for that period.

6(2) If an employee dies or ceases to be in service by reason of retirement, resignation, discharge, dismissal or removal from service in the course of an academic year, the allowance or reimbursement or hostel subsidy shall be admissible till the end of academic year in which the event takes place.

7. Children's Educational Allowance or Hotel Subsidy shall be admissible only in respect of children between the age limits of 5 and 20 years while Reimbursement of Tuition Fees shall be admissible only in respect of children between the age limits of 5 and 25 years, even if the child completes 20 years or 25 years, as the case may be, half way during the academic session. An employee shall not be eligible to draw Children's Educational Allowance, Reimbursement of Tuition Fees or Hostel Subsidy for more than two academic years in the same class.

8. Assistance under these Regulations shall be available upto 3 children born upto 31.12.1987 and shall be restricted to two children born thereafter.

9. The Children's Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fees or Hostel Subsidy, as the case may be, shall be admissible to an employee in respect of a child only if the child attends the school/college regularly.

Provided that no such allowance, reimbursement of tuition fee or hostel subsidy, shall be admissible in any case where the period of absence from the school/college without proper leave exceeds one month notwithstanding that the name of the child remains on the rolls of the school/college.

10. The Children's Educational Allowance, Reimbursement of Tuition Fees or Hostel Subsidy as the case may be, shall be admissible to an employee in respect of his children, regardless of the fact that any scholarship is received, provided that if freeship is awarded, reimbursement of Tuition Fees/Hostel Subsidy shall be admissible only to the extent of the fee actually paid.

CHILDREN'S EDUCATION ALLOWANCE:

11(1) An employee is eligible to draw Children's Education Allowance when he is compelled to send his child to a school/college away from the station at which he is posted and/or residing owing to the absence of a school/college of the requisite standard at that station.

EXPLANATION-1: "A' has his headquarters at the Harbour/Vasco-da-Gama and is residing at Margao. The Allowance will not be admissible if his children study in a school/college either at Harbour/Vasco-da-Gama or Margao.

EXPLANATION-2: Notwithstanding Regulation 11(1) above, the Children's Educational shall be admissible to an employee, who on transfer from one station to another, is compelled to keep his child/children studying in the final year of the Secondary/ Higher Secondary/Senior Secondary Classes at the old station for Board examination in the interest of continuity of studies.

11(2) For the purpose of this order, the following school/colleges shall not be deemed to be school/colleges of the requisite standard: -

- (a) Insofar as an Anglo-Indian child is concerned, a school/college not run by the Anglo-Indian community or a school/college not affiliated to the Council for Indian School Certificate Examination of the Indian Council of Secondary Education.
- b) A school/college run by a body of certain religious persuasion, which the child is prevented by the tenets of his religious persuasion from attending due to religious instructions being compulsorily imparted in such a school/college and
- (c) A school/college where teaching is conducted in a language different from the language of the child.

EXPLANATION (1):- The language of the child will be medium of instruction in the school where the child was getting educated earlier and in the case of child admitted in a school for the first time, the mother-tongue of the child by birth or by adoption.,

EXPLANATION (2): - The admissibility of Children's Education Allowance will have to be determined with reference to the standard of the school/college viz. Primary, Secondary or Higher Secondary or Senior Secondary and the medium of instruction and the language of the child and not due to the absence of a particular subject in a particular institution.

12. The allowance shall be admissible to an employee of the Board at a station where there is no school/college of the requisite standard, only if the nearest school/college of such standard is so situated that there is no convenient train or bus service to take the child from his residence near the time of the opening of the school/college and

bring him back not too long after the school/college is closed for the day and the journey by such train/bus service takes more than an hour.

13. If an employee is transferred from a station where there is no school/college of the requisite standard to a station where there is such a school/college and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child, he shall remain eligible for such allowance as long as the child studies in that school/college.

14. If a child of an employee is denied admission to a school/college of the requisite standard at the station, at which the employee is posted and/or residing because of there being no vacancy, or any other reasons, and the child is, compelled to attend a school/college away from the employee's place of posting and/or residence, the employee shall be entitled to the allowance as if there were no school/colleges of the requisite standard at that station.

EXPLANATION. — The availability of a vacancy in a school/college shall be determined with reference to the position existing at the time of the admission of the child in the school/college, whether it be at the start or in the middle of the session, in consultation with the competent educational authorities of the area and not on the basis of the certificate of the school/college authorities.

15. An employee in receipt of the allowance shall continue to be eligible to draw such allowance during any period, not exceeding four months.

- (1) When he may go and stay with the child in respect of whom the allowance is drawn while on leave or during suspension or temporary transfer.
- (2) When the child may come to live with the employee provided it is certified by a registered medical practitioner that the child is forced to remain away from studies due to illness, and
- (3) When the child may come to live with the employee during vacation, provided the child continues to be on the rolls of the school/college.

16. The allowance will be admissible at the rate of Rs.100/- per month per child for Primary, Secondary and Higher Secondary Classes (Classes I to XII).

17(1) The allowance shall be admissible to an employee throughout the year notwithstanding that no tuition fee is paid during the vacation.

(2) In the case of the child who is successful at the final secondary/higher secondary/senior secondary examination, the allowance shall be admissible to the employee upto the end of the month in which the examination is completed or upto the end of one month upto which the school/college fees are charged, whichever is later.

(3) In the case of a child who fails in the final secondary/higher secondary /senior secondary examination Board of Intermediate Examination or Pre-University Examination, but resumes his studies

the allowance shall be admissible to the employee for the period of vacation intervening provided that fees are paid for the period of vacation.

REIMBURSEMENT OF TUITION FEES.

18. An employee shall be eligible to the reimbursement of tuition fee payable and actually paid in respect of his child provided that no Children's Educational Allowance under these regulations is admissible to him.

19. The tuition fee payable and actually paid by an employee in respect of his child may be reimbursed subject to the following limits:

(a) Classes I to X..... Rs. 40/- per month per child.

(b) Classes XI to XII.... Rs. 50/- per month per child.

c) Classes I to XII – in respect of physically handicapped and mentally retarded children..... Rs. 100/- per month per child.

NOTE: Science fee upto the limit of Rs.10/- p.m. will be reimbursable in addition to the tuition fee in respect of children studying Classes IX to XII and offering Science subjects.

20. The reimbursement of tuition fee charged by a college run by a University or affiliated to a University for Pre-University/ two years class of an intermediate college or of a technical college of Engineering/ Medical or three years class of polytechnic or for a correspondence course shall, however, be reimbursed in full subject

to their being restricted to the rates prescribed by Government College for corresponding classes, including correspondence classes.

In cases where minimum qualification for admission in the three year diploma course in polytechnic is 10th class of the revised pattern of education and the student joins the polytechnic after passing X class of the revised pattern of education, the reimbursement of tuition fees shall also be allowed for the I, IInd and IIIrd year classes of the above course.

21. Notwithstanding anything to the contrary in these orders, tuition fee payable and paid in respect of physically handicapped or a mentally retarded child of an employee shall be reimbursed, subject to the following conditions: -

(a) The institution in which the child is studying is one, which is recognised or approved or aided by the Central Government or State Government or Union Territory Administration.

(b) The fees charged are approved by the Central Government or State Government or Union Territory Administration, as the case may be.

EXPLANATION: If the institution is recognised or approved or aided but the fees charged are not approved by Central or State Government or Union Territory Administration, the fee shall be subject to a ceiling of Rs.50/- per month.

22. HOSTEL SUBSIDY:

An employee shall be eligible to the grant of subsidy at the rate of Rs.300/- per month per child, if because of transfer he is obliged to keep his children in the hostel of a residential school/college far away from the station at which he is posted and/or is residing.

However, if the date of admission to the hostel is earlier than the date of transfer, and if such admission is made in anticipation of the transfer, the Hostel Subsidy may be made from the effective date of transfer.

23. The Hostel Subsidy shall be payable upto 10+2 stage in States and Union Territories, where the pattern of 10+2+3 has been adopted and upto higher secondary and senior secondary stage in other States and Union Territories, irrespective of the fact that the children study in a Kendriya Vidyalaya or any other recognised school/college.

24. The Hostel Subsidy shall not be admissible in respect of a child for whom children's Educational Allowance is drawn by an employee.

PROCEDURE FOR PAYMENT OF CHILDREN'S EDUCATION ALLOWANCE, REIMBURSEMENT OF TUITION FEES AND HOSTEL SUBSIDY"

25. An employee claiming Children's Educational Allowance, Reimbursement of Tuition fees or Hostel Subsidy shall furnish a certificate in the prescribed forms 1, 2, 3 and 4 as the case may be, to the Head of Department at the time of preferring his initial claim

and thereafter in the months of March and July every year. Where the employee is himself the Head of the Department, he shall furnish a certificate to the next higher authority.

NOTE: For reimbursement of tuition fees to an employee, a certificate from the Head of the Institution where the child is studying need not be insisted upon. However, at the time of accepting the initial claims, production of the cash receipt given by the school/college or counterfoil of the bank credit voucher, if the tuition's fee is paid through bank by the employee as a proof of having actually paid the tuition fee will be sufficient.

For the subsequent occasion, a declaration from the employee to the effect that he continues to incur the expenditure on tuition fee etc. should be accepted.. The employee may also be asked to certify that his child/children is/are actually studying in a recognised school/college and that he is actually incurring expenditure on tuition fee.

26. The Head of the Department in regard to employees working in his department and the next higher authority viz. the Chairman in regard to the Head of Department shall, after making such enquiry as may be considered necessary, issue a certificate indicating the amount of allowance admissible to the employee on the basis of which the allowance shall be drawn.

Provided that in the case of Children's Educational Allowance, it shall be permissible for the allowance being drawn on a provisional basis, pending verification as above, for short periods not exceeding three months, subject to an undertaking being obtained from the

employee that, if, as a result of verification, it established that a school/college of the requisite standard does exist at the station of posting/residence or near such station as referred to in Regulation No.12, he shall refund the allowance paid to him.

Provided further that the Head of Department or the next higher authority viz. the Chairman as the case may be may at his discretion, make enquiry at periodic intervals regarding admissibility of assistance under these orders.

27. The Head of Department shall certify on the pay bill that the certificates mentioned in Regulation No. 26 above have been obtained in respect of the employees covered in the pay bill.

•

28. An employee transferred from one station to another shall furnish a fresh certificate at the new station in case he continues to be eligible to draw Children's Educational Allowance or Hostel Subsidy.

29. The Head of Department should maintain a suitable record of the claims received, admitted/rejected and reimbursed in respect of such Port employee and make it available to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer along with the certificate and information furnished by the Port employees, the receipts of educational authorities in support of the claims preferred by them and other documents, if any. The record to be maintained shall be in the form as in Form No.5.

30. INTERPRETATION OF REGULATIONS:

If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Board.

31. REPEAL AND SAVINGS:

All rules corresponding to these Regulations and any orders issued in this regard from time to time and in force immediately before the commencement of these Regulations are hereby replaced.

Provided that any order or action taken under the regulations so replaced shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations

32. CENTRAL GOVERNMENT ORDERS/INSTRUCTIONS /RULES TO BE FOLLOWED IN THE APPLICATION OF THESE REGULATIONS:

In applying the foregoing regulations and in respect of matters not dealt within these Regulations, the Central Civil Services (Educational Assistance) Orders, 1988 and the orders/instructions of the Central Government issued thereunder from time to time shall be followed insofar as they are not inconsistent with the provisions in these Regulations, subject to such exceptions and modifications as the Board may from time to time determine.

